गाँवों में सुशासन पहल
प्रशासन गाँव की ओर

राकेश कुमार पाल

सुशासन यानी उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन । इस अवधारणा के तहत दिसंबर 2021 में 'प्रशासन गाँव की ओर' नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई। यह पहल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने, बेहतर सेवा-वितरण सुनिश्चित करने और प्रभावी शिकायत निवारण का एक महत्वपूर्ण और ठोस कदम है। लेखक के अनुसार, 'प्रशासन गाँव की ओर' केवल एक घोषणापत्र या प्रतीकात्मक अभियान नहीं है, बल्कि यह नागरिक-केंद्रित सुधार की दिशा में व्यावहारिक, परिणामोन्मुख और दीर्घकालिक प्रयास है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता को शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही का अनुभव कराना है, जिससे गाँवों में सुशासन का वास्तविक प्रभाव महसूस किया जा सके और स्थानीय प्रशासन अधिक उत्तरदायी एवं सशक्त बन सके।

गुड गवर्नेंस यानी सुशासन एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें ऐसा शासन शामिल है जो उत्तरदायी, पारदर्शी, संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त हो। भारत के ग्रामीण जीवन के बारे में महात्मा गाँधी का विज़न हमारे देश के दिल को छूता है, जहाँ ग्रामीण जीवन की लय भारत की आत्मा को परिभाषित करती है। गाँवों में सुशासन सिर्फ़ एक नीतिगत लक्ष्य नहीं है बल्कि देश की तरक्की की नींव है। स्वतंत्रता के पश्चात से सत्तारुढ़ सरकारों ने ग्रामीण भारत को बेहतर बनाने का वादा तो किया लेकिन लगातार चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत सरकार ने 20 दिसंबर, 2021 को 'प्रशासन गाँव की ओर' अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के दरवाजे तक प्रभावी शासन पहुँचाना है। इसका लक्ष्य प्रशासन की सेवाओं को निचले स्तर तक पहुँचाना है।

विरासत का सम्मान

भारत की शासन यात्रा को उन नेताओं से प्रेरणा मिली है, जिन्होंने माना कि जनसेवा पारदर्शी, उत्तरदायी और सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। इन दूरदर्शी नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन यानी गुड गवर्नेंस में अपने

लेखक प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नई दिल्ली में सूचना अधिकारी हैं। ईमेलः rakesh.pal@gov.in

25 दिसंबर, 2014 से पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की जयंती को देशभर में 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि शासन केवल एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समानता और दक्षता बनाए रखने के लिए एक नैतिक प्रतिबद्धता है। यह "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के सिद्धांत पर चिंतन करने का भी अवसर है - एक ऐसे प्रशासन का आह्वान जो नियंत्रण करने के बजाय सशक्त बनाए।

पक्के विश्वास के लिए जाने जाते हैं। सन् 1998 से 2004 के बीच उनके नेतृत्व ने नागरिक-केंद्रित सुधारों की नींव रखी जो आज भी गवर्नेंस का मार्गदर्शन करते हैं। वर्ष 2014 से, 25 दिसंबर को वाजपेयी जी की जयंती को पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि गवर्नेंस सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि बराबरी और कुशलता बनाए रखने की एक नैतिक प्रतिबद्धता है। यह 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांत पर विचार करने का अवसर भी है–ऐसा प्रशासन जो नियंत्रण ही नहीं बल्कि सशक्तीकरण पर आधारित हो। सुशासन दिवस हमें इसके महत्व को समझने, इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अध्ययन करने और लोकतांत्रिक मूल्यों पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करने का अवसर देता है ताकि एक ऐसा प्रशासनिक ढाँचा विकसित किया जा सके जो न केवल समावेशी हो बल्कि 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के सिद्धांतों को भी मज़बूती से स्थापित करे। यह उन अवसरों में से एक है जब लोकतंत्र की भावना जीवंत होती है और वैश्विक स्तर पर सुशासन को बढ़ावा देने के प्रयासों को गति मिलती है।

सुशासन दिवस हमें आर्थिक सुधारों, अवसंरचना विकास और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने का भी अवसर प्रदान करता है। यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुशासन किसी भी राष्ट्र की प्रगति का मूल तत्व है। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सुशासन दिवस का उत्सव न केवल उनकी विरासत का सम्मान करता है बल्कि उन सिद्धांतों को भी सुदृढ़ करता है जिनके लिए वे खड़े रहे।

ज़मीनी स्तर तक गवर्नेंस

वर्ष 2021 में, सरकार ने सुशासन के सिद्धांतों को ज़मीनी स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए मौजूदा सुशासन पहल को और सशक्त करने हेतु 'प्रशासन गाँव की ओर' नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में शासन को और अधिक समीप लाना था चाहे वह जन-शिकायत निवारण हो या सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार हो।

वर्ष 2021 के संस्करण के दौरान ज़िला कलेक्टरों ने 'सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाएँ और सफल कहानियाँ' पोर्टल पर अपलोड कीं। NCGG / IIPA के आँकड़ों के अनुसार इस दौरान लगभग 2.89 करोड़ सर्विस डिलीवरी संबंधित आवेदन दर्ज़ किए गए। इसके बाद 20–25 दिसंबर, वर्ष 2022–24 के बीच 'प्रशासन गाँव की ओर' पहल पर आधारित कार्यक्रमों को भी समान सफलता मिली।

2024 में हासिल की गई कुछ शानदार उपलब्धियां:

श्रेणी	आँकड़ा
सर्विस डिलीवरी के तहत निपटाए गए आवेदन	2.99 करोड़
राज्य पोर्टलों के ज़रिए शिकायतों का समाधान	15 लाख
CPGRAMS के ज़रिए हल की गई शिकायतें	3.4 लाख
देशभर में आयोजित जनसेवा शिविर	51,000+
शासन में प्रलेखित नवाचार	1,167
तैयार किए गए ज़िला विज़न@100 दस्तावेज़	272

700 से अधिक ज़िलों में फैले आयोजनों के साथ 'प्रशासन गाँव की ओर' भारत का सबसे बड़ा जन-केंद्रित सुशासन अभियान बन गया। उत्तर प्रदेश और बिहार के समतल मैदानों से लेकर जम्मू-कश्मीर की घाटियों और असम की पहाड़ियों तक स्थानीय समुदायों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे यह नागरिक सहभागिता और प्रशासनिक संकल्प का एक उत्सव बन गया।

ग्रामीण भारत के लिए मज़बूत नींव का निर्माण

'प्रशासन गाँव की ओर' मूल रूप से पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:

- **विकेन्द्रीकृत शासन**

पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति देना सुनिश्चित करता है कि लोगों की आवाज़ें स्थानीय भविष्य का निर्माण करें। उनकी क्षमता और स्वायत्तता को मज़बूत करना सतत विकास की कुंजी है।

- **जनसेवाओं की उपलब्धता**

कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) और ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ग्रामीण नागरिक आधार पंजीकरण, भूमि

अभिलेख और कल्याणकारी योजनाओं जैसी सेवाओं तक तेज़ी और कुशलता से पहुँच सकते हैं।

- **डिजिटल सशक्तीकरण**

डिजिटल इंडिया मिशन इंटरनेट पहुँच को बेहतर बनाकर और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर ग्रामीण जीवन को बदल रहा है। इससे गाँव के लोग शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता के नए अवसरों से जुड़ पा रहे हैं।

- **सहभागी शासन**

शासन तभी फलता-फूलता है जब लोग सक्रिय सहभागिता करें। ग्राम सभाएँ अब ऐसा मंच बन गई हैं जहाँ ग्रामीण विचार साझा करते हैं, समस्याएँ उठाते हैं और प्रशासन को जवाबदेह बनाते हैं जिससे विश्वास और समावेशन को बढ़ावा मिलता है।

- **कल्याणकारी योजनाएँ**

प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत किया है और जीवन-स्तर एवं सामुदायिक अवसंरचना में सुधार सुनिश्चित किया है।

वास्तविक प्रभाव

अब प्रश्न उठता है कि क्या 'प्रशासन गाँव की ओर' कार्यक्रम सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? कार्यक्रम के आर्थिक पहलुओं

प्रशासन गाँव की ओर उद्देश्य

- गाँव और शहर का फासला कम करना
- गाँवों में स्थानीय शासन को मज़बूत करना
- ग्रामीण लोगों को सशक्त बनाना
- सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुँचाना

को ध्यान में रखने पर यह स्पष्ट होता है कि इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ी है, शासन को ज़मीनी-स्तर तक ले जाने का अवसर मिला है, शिकायत निवारण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, स्थानीय-स्तर पर सुशासन की सर्वोत्तम प्रथाएँ संस्थागत रूप से स्थापित हुई हैं और शासन का विकेन्द्रीकरण संभव हुआ है जो आम नागरिकों की जरूरी माँग रही है।

नागरिकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए यह योजना है कि अगले वर्ष इस कार्यक्रम को देश के और भी दूरदराज़ क्षेत्रों तक ले जाया जाए और इसमें अधिक नागरिक-कल्याणकारी योजनाएँ शामिल की जाएँ।

आगे की राह

सुशासन का वास्तविक अर्थ यही है कि हर नागरिक को एक उत्तरदायी और संवेदनशील सरकार का अनुभव हो, चाहे वह किसी महानगर के केंद्र में रहता हो या किसी सुदूर गाँव में। 'प्रशासन गाँव की ओर' ने यह सिद्ध किया है कि शासन प्रभावी होने के साथ-साथ सहानुभूतिपूर्ण भी हो सकता है, जहाँ तकनीक और मानवीय संवेदनाएँ दोनों साथ-साथ चलती हैं।

सुशासन कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिसे केवल एक सप्ताह मनाया जाए; यह उत्कृष्टता की निरंतर खोज है। 'रामराज्य' अर्थात् न्याय, समानता और समृद्धि के विज़न को साकार करने के लिए प्रत्येक अधिकारी, नीति निर्माता और नागरिक को राष्ट्र निर्माण की ज़िम्मेदारी साझा करनी होगी। जब शासन लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाता है तो राष्ट्र निर्माण एक सामूहिक दायित्व में बदल जाता है। ❑